



वानिकी समाचार

वन विभाग राजस्थान का मासिक पत्र

वर्ष : 26

अंक : 6

जून-2009

पृथ्वी को यदि बचाना है।
तो पेड़ अधिक लगाना है।।

17 जून : विश्व मरुस्थल नियंत्रण दिवस

शोकना होगा बढ़ता मरुस्थलीकरण

■ यू.एम. सहाय



प्रतिवर्ष 17 जून का दिन पूरे विश्व में "विश्व मरुस्थल नियंत्रण दिवस" के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में पेरिस में आयोजित एक सम्मेलन में हुई थी। इसके पीछे मूल भावना यही है कि अधिक से अधिक संख्या में समाज के सभी वर्गों-स्त्री, पुरुष व बच्चों आदि को मरुस्थलीकरण की समस्या के प्रति जागरूक बनाया जावे एवं उन्हें अवगत कराया जावे कि इस समस्या का समाधान जन-सहभागिता एवं प्रत्येक स्तर पर सहयोग के बिना संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2009 की थीम "भूमि एवं जल संरक्षण-हमारे सबके भविष्य को सुरक्षित बनाना" रखा गया है। यह थीम 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों को भी इंगित करती है। बिना भूमि, मृदा एवं जल के संरक्षण के मानव जाति के

भविष्य को सुरक्षित किया जाना संभव नहीं है। जहां एक ओर मरुस्थलीकरण से पर्यावरणीय हास एवं प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होता है वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण प्रक्रिया को तेजी प्रदान करता है, गरीबी व भूखमरी बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन से पूरे विश्व एवं समूची मानव जाति पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

वैज्ञानिकों के मतानुसार यदि ग्रीन हाउस गैसों के विसर्जन को रोकने के संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो वर्ष 2100 के अन्त तक पृथ्वी का तापमान 2.0 डिग्री से. से 5.0 डिग्री से. तक बढ़ जावेगा। पृथ्वी के तापमान बढ़ने की यह दर पिछले 10,000 वर्षों में सबसे अधिक है। जो निश्चित रूप से एक चिन्ता का विषय है।

शेष पृष्ठ 3 पर.....

सम्पादकीय... पौधारोपण

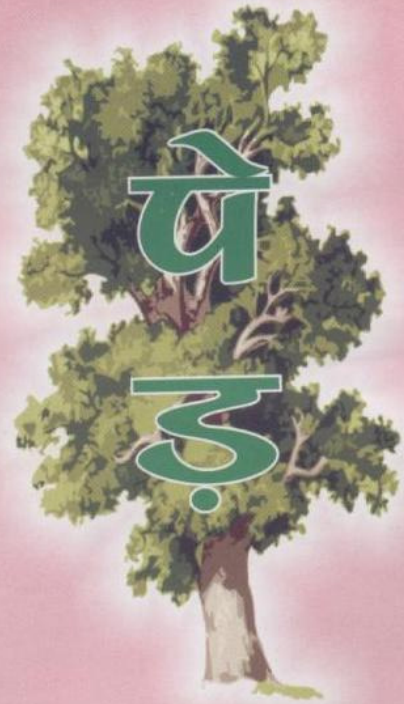
वर्षाकाल पौधारोपण और पौध वितरण का समय होता है। इस समय एक ओर पौधशाला में विकसित किये गये पौधों का सार्वजनिक रूप से वितरण-विक्रय करना होता है तो दूसरी ओर छोटे पौधों की ग्रेडिंग करके उनका संधारण भी करना होता है। वर्तमान युग में शहरी क्षेत्रों में सजावटी तथा शोभाकारी पौधों की बड़ी मांग रहती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छाया, ईंधन तथा फलदार पौधों की मांग रहती है। अतः आमजन को उसकी इच्छानुसार पौधे उपलब्ध कराना जरूरी है ताकि वे वृक्षारोपण अभियान में भागीदारी निभा सकें।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषित हरित राजस्थान कार्यक्रम में पौधारोपण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नरेगा कार्यक्रम से जोड़ा गया है। इससे विभाग को जन सहभागिता से पौधारोपण करने तथा हरियाली विकास का एक शुभ अवसर मिला है। वस्तुतः वर्षाकाल में स्कूलों, कालेजों तथा शिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को प्रेरित कर वन महोत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि युवावर्ग को पौधारोपण अभियान से जोड़ा जा सके। शैक्षणिक संस्थानों/विद्यालयों में बहुत अधिक जमीन उपलब्ध होती है जिसका उपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जा सकता है।

यद्यपि विभाग में स्टाफ की कमी की समस्या है फिर भी यथासंभव एक-दो वनकर्मियों को पौधारोपण की विधियों का प्रशिक्षण देने हेतु स्कूलों-कॉलेजों में जाना चाहिये अथवा पौधारोपण कार्यक्रम से पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि जो पौधा वे रोपित कर रहे हैं, वह भलीभांति स्थापित एवं विकसित हो सकें।

इस अवसर पर छात्राओं के समूहों को भी पौधारोपण अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

वन महोत्सव का आयोजन पूरे वर्षाकाल में चलाया जाना चाहिए। इससे न केवल वृक्षारोपण के प्रति वातावरण का निर्माण होगा बल्कि वन संरक्षण के प्रति भी जनमत का भाव बनेगा। इस कार्य को जितनी निष्ठा और समर्पित भाव से किया जावेगा उतना ही विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति होगी।



□ सोनल अग्रवाल

पेड़ों से आती हरियाली,
घर-घर में होती खुशहाली,
पेड़ हमारे रक्षक हैं,
हम भी उनके समर्थक हैं।
पेड़ हमें जीवन देते हैं,
पर हम इनका जीवन लेते हैं।
नहीं चाहिए पेड़ काटना,
अगर हमको है जीवन जीना।
पेड़ लगाना हमारा धर्म है,
क्योंकि ये हमारे जीवन
के अभिन्न अंग हैं।
पेड़ से बनी चीजों का
कम करो उपयोग,
ताकि पेड़ों को कटने से,
बचाने में हो सके सहयोग।
पेड़ हमारे जीवन दाता,
इन्हें काटने पर होता
हमारा घाटा।
इसलिए ज्यादा से
ज्यादा पेड़ लगाओ,
जीवन को खुशहाल बनाओ।

पेज 1 का शेष.....

आज मरुस्थलीकरण एक विश्व व्यापी समस्या है, क्योंकि इसके प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही पहलू हैं। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध की गई लड़ाई गरीबी दूर करने में सहायक है। इसमें हम सभी अपने-अपने स्तर पर शामिल हो सकते हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग, जो प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के प्रति स्वाभाविक रुचि रखते हैं, वे इस सामूहिक लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले योद्धा हो सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों एवं युवा वर्ग को पर्यावरणीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने एवं उनके सम्भावित समाधान खोजने के लिए प्रेरित करने में हमारी शिक्षा प्रणाली द्वारा टिकाऊ विकास की विचारधारा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।



मरुस्थलीकरण रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुसार मरुस्थलीकरण शुष्क, अल्प-शुष्क एवं उप-आर्द्र क्षेत्रों में विभिन्न कारकों, जैसे जलवायु विविधता और मानवीय गतिविधियों द्वारा, भूमि का अपघटन है। भूमि अपघटन सभी स्थानों पर होता है लेकिन जब यह शुष्क भूमि में होता है तब इसे मरुस्थलीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मरुस्थलीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है जो शुष्क एवं क्षयशील पारिस्थितिकी तंत्रों में देखी जा सकती है। यह स्थलीय क्षेत्रों (ऊपरी मिट्टी की परत, भूमि, भू-जल स्त्रोतों एवं सतही जल बहाव), पशुओं, वनस्पतियों, मानव बस्तियों एवं सुविधाओं (जैसे खेतों और बांधों) को प्रभावित करती है।

वर्तमान में मरुस्थलीकरण केवल विकासशील देशों की चिन्ता का विषय नहीं है बल्कि विकसित देश भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि भूमि के कृषि के लिए अनुपयुक्त होने के कारण लोग अपनी भूमि छोड़कर दूसरे देशों में विशेषकर विकसित देशों में प्रवास कर जाते हैं। इससे राहत कार्यों एवं मानवीय सहायता पर काफी बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। कुल मिलाकर विश्व के 110 से अधिक देश शुष्क भूमि मरुस्थलीकरण के सम्भावित खतरे से ग्रसित है। मरुस्थलीकरण से प्रभावित सबसे अधिक शुष्क भूमि (74%) उत्तरी अमेरिका में है।

क्यों होता है मरुस्थलीकरण?

मरुस्थलीकरण के मुख्य तात्कालिक कारणों में चार मानवीय गतिविधियां प्रमुख हैं :-

1. अत्यधिक सघन खेती से मृदा की उर्वरता समाप्त होना,
2. अत्यधिक चराई से वनस्पति आवरण, जो मृदा की अपरदन से सुरक्षा करता है, का नष्ट होना
3. वन, जो मृदा को भूमि से बांधे रहते हैं, का नष्ट होना तथा
4. अपर्याप्त जल निकासी वाली सिंचाई व्यवस्था से उपजाऊ भूमि का लवणीय हो जाना

इसके अतिरिक्त शिक्षा एवं ज्ञान की कमी, विकासशील देशों की प्रतिकूल व्यापार परिस्थितियां और अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण मरुस्थलीकरण के प्रभावों को बढ़ाते हैं।

मरुस्थलीकरण के पर्यावरणीय प्रभाव

यदि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से पर्यावरण पर पड़ने वाले अनेकानेक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभावों को देखें तो अनेक ज्वलंत समस्याएँ उभर कर सामने आती हैं। यथा, मृदा क्षरण, जल संकट एवं जैव विविधता की हानि आदि।

गरीबी बढ़ाता है मरुस्थलीकरण

मरुस्थलीकरण के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दुष्प्रभाव भी गहरे होते हैं। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चे-खुचे प्राकृतिक संसाधनों का

जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही होती आ रही है किन्तु मानव गतिविधियों, अनियोजित विकास व ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक विसर्जन आदि के कारण पृथ्वी पहले की तुलना में बहुत तीव्र दर से गर्म होती जा रही है जिससे विभिन्न ईको सिस्टम, जल संसाधन, खाद्य संसाधन व मनुष्य के स्वास्थ्य पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बाढ़ व अकाल की घटनाओं में वृद्धि हो रही है हिम खण्ड (ग्लेशियर्स) पिघल रहे हैं व विभिन्न प्रकार की नई-नई बीमारियाँ फैल रही हैं। यह समस्या वास्तव में गम्भीर है और यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि इसके निराकरण के लिए ठोस उपाय किये जावें। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रीनहाउस गैसों के विसर्जन में कमी लाई जावे वनों के संरक्षण एवं विकास पर समुचित ध्यान दिया जावे। क्योंकि वन अकाल की विभीषिका को कम करने एवं मरुस्थलीकरण को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

अत्यधिक दोहन करते हैं जिससे भूमि के खराब होने का दुष्प्रभाव बढ़ता जाता है। अतः गरीबी मरुमरुस्थलीकरण का कारण एवं परिणाम दोनों ही हैं।

सूखा एवं भूमि की उर्वरता कम होने से ग्रामीण जनसंख्या को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस पलायन से शहरी पर्यावरण में तो समस्याएं आती ही हैं साथ ही उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जो सूखे से अप्रभावित हैं, नये लोगों के आने से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में जीवन की परिस्थितियां शुरू में बेहतर होती हैं परन्तु अन्त में काफी कठिन हो जाती हैं। यह एक अत्यन्त विकराल एवं जटिल पर्यावरणीय समस्या है। जिसका समाधान आसान नहीं है। फिर भी इस समस्या के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रयास किये जा रहे हैं। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संघर्ष की दिशा में सबसे पहला ठोस प्रयास वर्ष 1968-1974 में साहेल के

सबसे बड़े अकाल एवं सूखे के बाद किया गया, जिसमें दो लाख व्यक्तियों एवं करोड़ों पशुओं की मृत्यु हुई थी।

इससे प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों की पूर्ण प्रतिबद्धता एवं भागीदारी आवश्यक है। शुष्क क्षेत्रों के लोग इस संघर्ष में स्वयं ही सबसे उत्तम संसाधन हैं। क्योंकि किसी अन्य की अपेक्षा वे अपनी भूमि के बारे में बेहतर जानते हैं। इस संबंध में उनकी दक्षता अन्य क्षेत्रों के लोगों की तुलना में अधिक होती है। क्योंकि उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने का अभ्यास होता है।

मरुस्थलीकरण रोकने में प्रत्येक स्त्री, पुरुष एवं युवा वर्ग के योगदान की आवश्यकता है। मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक समाज के सभी स्तरों के व्यक्ति एकजुट नहीं होते।

“विशाल भारतीय मरुस्थल” जिसे **“थार मरुस्थल”** भी कहा जाता है, विश्व के सात मरुस्थलों में से एक है तथा सम्भवतः सबसे अधिक जन घनत्व वाला एवं मनोहारी मरुस्थल है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी औसत जनसंख्या घनत्व 161 व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर है अधिकतम जनसंख्या घनत्व 323 व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर झुंझुनूं जिले में एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 13 व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर जैसलमेर जिले में है। अरावली पर्वतमाला राज्य को दो असमान भागों में विभाजित करती है। यद्यपि सम्पूर्ण राज्य शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्र के अन्तर्गत आता है फिर भी 12 जिलों जैसे- जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सीकर, चुरू, झुंझुनूं, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को सम्मिलित करने वाला अरावली श्रेणी का उत्तर-पश्चिम भाग वास्तविक रूप में थार मरुस्थल का प्रतिनिधित्व करता है। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.18 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात राज्य में फैला हुआ है। इसका प्रमुख शुष्क एवं बड़ा भाग केवल राजस्थान राज्य में है जिसका कुल क्षेत्रफल 12 जिलों में लगभग 2.08 लाख वर्ग किलोमीटर है।

काले हिरणों के लिए 195 बीघा जमीन अधिगृहित होगी

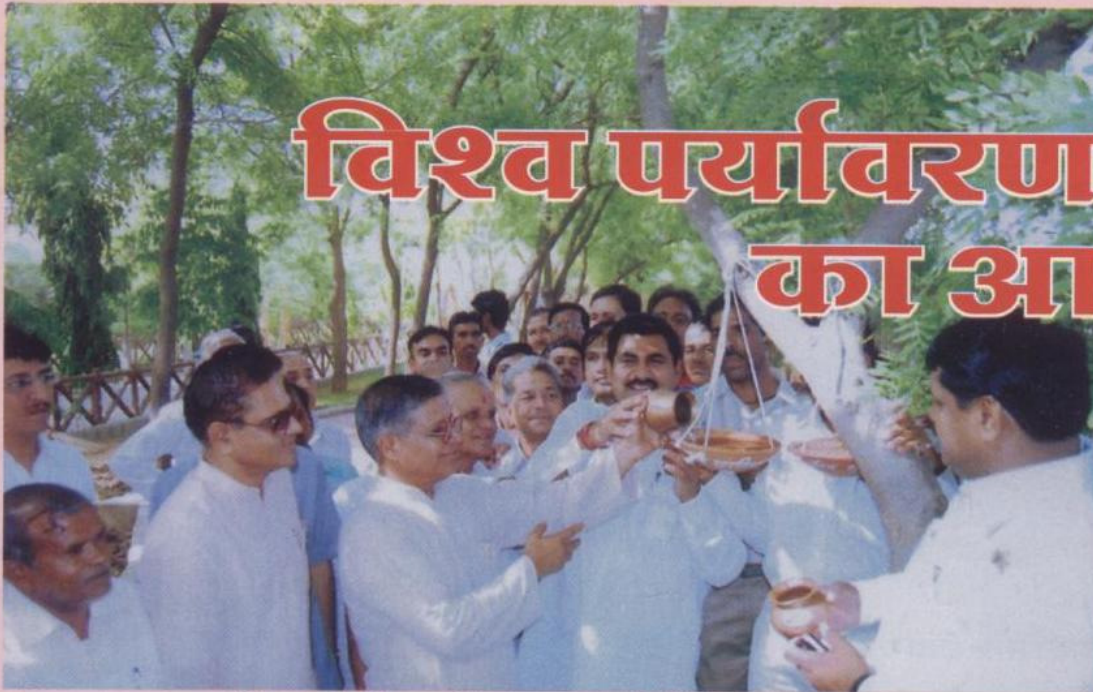
काले हिरणों की शरणस्थली के लिए तालछापर अभयारण का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए 195 बीघा जमीन अधिगृहित की जाएगी। इस अभयारण्य को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

वन राज्यमंत्री रामलाल जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। अभयारण्य का विस्तार होने से काले हिरणों को स्वच्छंद विचरण में मदद मिलेगी। अभयारण्य में करीब दो हजार काले हिरण हैं। अभयारण्य में देसी-विदेशी परिंदे भी बड़ी संख्या में तीन-चार महीनों का प्रवास करने आते हैं। जमीन अधिग्रहण के लिए 170 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा जाएगा। अभयारण्य में काले हिरणों की सुरक्षा के लिए करीब एक किमी लंबी और 6 फुट ऊंची नई दीवार भी बनाई जाएगी। अभयारण्य में पर्यटकों के ठहरने के लिए निर्माणाधीन रेस्ट हाउस का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा।

राज्यमंत्री ने बताया कि तालछापर से प्रमुख लोगों से चर्चा करके स्थानीय महाराजा की कोठी में संचालित सीनियर सैकंडरी स्कूल के अन्य स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। इस स्कूल के दूसरी जगह स्थानांतरित

होने पर यह कोठी पर्यटकों के लिए विकसित की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मा. भंवरलाल मेघवाल से चर्चा की जाएगी। तालछापर अभयारण्य मा. मेघवाल के चुनाव क्षेत्र सुजानगढ़ में है।





भीलवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन

अभियान, हरा भरा हो राजस्थान''
स्लोगन लिखकर प्रदेश की जनता को
वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण का
संदेश दिया।

समारोह की अध्यक्षता करते
हुए माण्डलगढ़ के विधायक प्रदीप
कुमार सिंह ने कहा कि विकास की
लगन हो तो शमशान भी विकसित
उद्यान का रूप ले लेता है, यहां

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण, श्री रामलाल जाट, पक्षियों के लिए जल पात्र बांधते हुए।

भीलवाड़ा। वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री रामलाल जाट ने वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु योजनाबद्ध ढंग से सार्थक प्रयासों की महती आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि आने वाले समय में सभी के समन्वित सहयोग से राजस्थान में वन विकास के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किये जायेंगे।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में पीपुल फार एनीमल एवं वन विभाग के तत्वावधान में स्थानीय पंचमुखी मोक्षधाम परिसर में आयोजित विशाल संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान को हरा-भरा बनाने की मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की परिकल्पना को मूर्तरूप देने के लिए हम सब को कृत संकल्प होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पीपुल फार एनीमल्स जैसी सेवाभावी संस्था पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अति प्रशंसनीय प्रयास कर रही है। संस्था ने प्रदेश में पेड़-पौधे, पशु-पक्षी व पानी एवं प्रकृति संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय आयाम प्रस्तुत किये हैं।

जाट ने मुक्तिधाम पर हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों का अवलोकन किया और कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने पीपुल्स फार एनीमल्स संस्था के तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण एवं जल संरक्षण व प्रबंधन पर पोस्टर व निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह वितरण किये। पक्षी प्रेमी राधेश्याम चेचाणी, प्रदीप अग्रवाल, विद्यासागर सुराणा को पक्षियों के दाना पानी के लिए परिण्डों का वितरण किया गया। उन्होंने मुक्तिधाम परिसर में पक्षियों के दाना पानी के लिए परिण्डे भी लगाये।

प्रारम्भ में केनवास पर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री ने "जन जन का यह

मुक्तिधाम में चारों ओर हरियाली देखकर लगता है कि सही स्थान पर विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम करके लोगों में हरियाली बढ़ाने के लिए जन चेतना जगाने का सार्थक प्रयास किया गया है।

उन्होंने प्रत्येक नागरिक को प्रकृति के बनाये नियमों के अनुसार संतुलन बनाये रखने का आह्वान किया। उन्होंने पीएफए संस्था के कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की।

पीपुल फार एनीमल्स संस्था के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राजस्थान को हरा भरा प्रदेश बनाने का सपना अवश्य साकार हो सकेगा और वनों का तेज गति से विकास होगा और प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए पिछले वर्षों में जो कार्य नहीं हो सके उन्हें गति मिलेगी, ऐसी अपेक्षा है।



पत्र-परिपत्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1 (72) 09/ग्रीन राजस्थान/विकास/प्रमुवसं/8630-41

दिनांक : 9.6.09

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,

जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/
वन्य जीव, जयपुर/वन्य जीव, उदयपुर/बनास परियोजना, जयपुर/
परियोजनाएँ, कोटा/विभागीय कार्य, जयपुर

विषय : हरित राजस्थान कार्यक्रम के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार के हरित राजस्थान के संकल्प की क्रियान्विति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 22.5.09 में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए सम्पूर्ण राज्य में सघन प्रचार-प्रसार कर अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। इस अभियान में वन विभाग के अलावा अन्य राजकीय विभागों एवं पंचायतों द्वारा भी राजकीय भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाये जायेंगे। इस अभियान के लिए निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं-

1. नर्सरियों में फार्म फोरेस्ट्री के अन्तर्गत तैयार किये गये छायादार/सजावटी वृक्ष प्रजाति के पौधों को लोगों को वितरित नहीं कर **हरित राजस्थान** कार्यक्रम के लिए राजकीय विभागों एवं पंचायतों हेतु आरक्षित रखा जावे।
2. संग्रहित किये गये बीजों को विभागीय योजनाओं में वृक्षारोपण में उपयोग में लिए जाने के अलावा हरित राजस्थान कार्यक्रम के लिए भी आरक्षित रखा जावे।
3. कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध योजना तैयार की जावे।
4. हरित राजस्थान के कार्यक्रम का मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जावे। इसके लिए सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय की सेवायें भी ली जा सकती हैं।
5. ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं, मीडिया प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी इस अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ा जाना उपयुक्त होगा।
6. स्काउट गाइड्स, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एन.सी.सी. से संबंधित विद्यार्थियों को योजना में सम्मिलित किया जावे एवं उनका सहयोग लिया जावे।

भवदीय

ह.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर

ग्रामीण विकास मंत्री ने किया पौधा रोपण



भीलवाड़ा। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री भरत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान को हरा-भरा प्रदेश बनाने के प्रयासों में आम जन भी भागीदार बनें। उन्होंने वर्षा ऋतु के दौरान पौधारोपण कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में चलाने की जरूरत बताते हुए कहा कि जितने अधिक पेड़ होंगे उतना ही पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और वर्षा की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

भरत सिंह ने भीलवाड़ा में हनुमान कॉलोनी स्थित प्रकृति विहार में पौधारोपण करते हुए यह बात कही। ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रकृति विहार में पौधा लगा अवलोकन करते हुए कहा कि प्रकृति विहार पर्यावरण शिक्षा की दृष्टि से अच्छा केन्द्र है। पीपुल फॉर एनीमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने बताया कि यहां छात्र-छात्राओं को पर्यावरण शिक्षा एवं पौधारोपण से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने व पर्यावरण व जल संरक्षण व प्रबंध से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं।

श्री भरत सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों ने जन चेतना जगाने एवं नवयुवकों को इससे जोड़ने की जरूरत बताई।

विश्व पर्यावरण दिवस पर वन मंत्री ने बांधे पक्षियों के लिए जलपात्र



जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री रामलाल जाट ने स्मृति वन, जयपुर में पौधारोपण किया और पक्षियों के लिए वृक्षों पर जलपात्र भी बांधे।

इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले एक स्टीकर का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अभिजीत घोष सहित अनेक वनाधिकारीगण, प्रकृति प्रेमी तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

वन मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रामलाल जाट ने वनाधिकारियों को निर्देश दिये कि हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए ठोस कार्य योजना बनायें तथा हरित राजस्थान की पंचवर्षीय कार्य योजना को जिला प्रशासन के सहयोग से तैयार करें ताकि राज्य में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जा सके।

वन भवन में 10 जून को वन विभाग द्वारा वानिकी विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य में विषम जलवायु तथा भूमि की उपलब्धता को देखते हुए कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग को वनाच्छादित किया जा सकता है। वन मंत्री ने कहा कि हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष में एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 650 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य पूर्ण किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि ग्राम्य वन एवं सुरक्षा प्रबंध समितियों के माध्यम से एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के संकल्प को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 20 हजार हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वन विकास अभिकरण के माध्यम से भी 9500 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया जाना चाहिये, जिससे राज्य में सघन वृक्षारोपण हो सके।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने बताया कि फार्म फोरेस्टो के तहत इस वर्ष 45 लाख पौध विभागीय पौधशालाओं में तैयार किये गये हैं। उन्होंने वनाधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य की विभिन्न सड़कों के किनारे नरेगा योजना के अन्तर्गत आगामी पांच वर्ष में लगभग 23 हजार किलोमीटर लम्बी पट्टी पर वृक्षारोपण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रमों में ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया प्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी वृक्षारोपण अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ा जायेगा।

उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में जन जागृति के लिए तथा स्काउट, गाईड्स, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एन.सी.सी. सदस्यों व विद्यार्थियों को योजना में सम्मिलित कर उनका पूर्ण सहयोग लिया जायेगा। बैठक में वन सचिव बी.एल. आर्य, प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक अभिजीत घोष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन जीव प्रतिपालक आर.एन. मेहरोत्रा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

नरेगा में शामिल हरित राजस्थान कार्यक्रम

हरित राजस्थान योजना की सफल क्रियान्विति में सहयोग लेने के लिए प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी एस. अहमद की अध्यक्षता में 10 जून को वन विभाग के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जी.एस. संधु ने बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत प्रदेश को हरा-भरा बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के साथ ही पेयजल की गम्भीर समस्या से निजात पाना है।

संधु ने बताया कि इस योजना में भागीदारी के साथ लोगों को यह सोचना है कि प्रदेश में जलस्तर कैसे बढ़े और कैसे ज्यादा वर्षा हो? उन्होंने कहा कि जल स्तर नीचे जाने से पीने के पानी की आपूर्ति की गम्भीर समस्या बनी हुई है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सघन वृक्षारोपण की इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में शामिल किया है। पांच साल तक चलने वाली इस योजना में पौधारोपण के साथ रख-रखाव की व्यवस्था भी है।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से स्वैच्छिक संगठनों, अधिकारी एवं कर्मचारी संस्थाओं सहित समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जाएगा। संधु ने स्वैच्छिक संगठनों को आह्वान किया कि वे जनजागरण के साथ वृक्षारोपण एवं रख-रखाव के कार्य में सक्रिय रूप से जुड़े।

बैठक में विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों ने योजना को राज्य की दीर्घकालीन विकास के लिए मील का पत्थर बताते हुए भरोसा दिलाया कि प्रदेश को हरा-भरा बनाने के इस काम में संगठन सक्रिय भूमिका निभायेंगे। बैठक में प्रमुख शासन सचिव (वन) बी.एल. आर्य, शासन सचिव एवं आयुक्त ई.जी.एस. राजेन्द्र भाणावत, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अभिजीत घोष, वरिष्ठ वन अधिकारी एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अनुरोध :

वानिकी समाचार में प्रकाशनार्थ आलेख, छायाचित्र, विभागीय गतिविधियों की जानकारी, साझा वन प्रबन्ध की सफल कहानियां, कविताएं तथा अन्य सामग्री प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। यह सामग्री ई-मेल से भी भेजी जा सकती है।

इस पत्रिका के अंक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

- सम्पादक

Book-Post

